

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा  
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम आर.ए.एस

मुकदमा नं० 454/2017

प्रार्थी :-

1. लतीब खां पुत्र घुमैखां जाति मुसलमान निवसी नवातला
2. श्रीमति मलू पत्नि लतीब खां जाति मुसलमान निवासी नवातला तह० पचपदरा  
बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. करीमखां पुत्र कादरखां
2. निजाम खां पुत्र कादरखां
3. दावदखां पुत्र कादरखां
4. मौमोवेया कादरखां
5. बचू पुत्र रेमाखां
6. मोहमदखां पुत्र बोराखां
7. मृतक नसीरखां पुत्र हेमुखां के कायम मुकाम  
7/1 हबीबखां पुत्र नसीरखां  
7/2 लादुखां पुत्र नसीरखां  
7/3 माफेखां पुत्र नसीरखां  
7/4 मुकेखां पुत्र नसीरखां  
7/5 कवरू पत्नि नसीरखां सभी जातियान मुसलमान प्रतिवादी सं० 7/3 व 7/4 नाबालिंग  
जहीये कुदरती वली माता कवरू पत्नि नसीरखां सभी निवासीयान जवाहरपुरा तह० पचपदरा
8. मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक शाखा पचपदरा
9. राजस्थान राज्य द्वारा जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम  
बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

- उपस्थित :-
1. श्री अचलाराम थोरी प्रार्थी वकील
  2. श्री उमरदीन विप्रार्थी वकील

आदेश

दिनांक 28.12.2017

प्रार्थना पत्र के तथ्य सक्षिप्त में इस प्रकार है कि सरहद मौजा भगतलाई पटवार क्षेत्र नवातला की राजस्व सीमा में खेत खसरा सं. 546 रकबा 108 बीघा 09 विस्वा अवस्थित है, उपरोक्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण का सहसंयुक्त सामलाती में 1/3 हिस्सा बराबर 36 बीघा 03 विस्वा रहा व है। उपरोक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण की सहसंयुक्त सामलाती की कृषि भूमि रही है, जिसमें प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा रहा है, तथा उपरोक्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण एवं का 1/3 हिस्सा पर कब्जा काश्त कायम रहा व है, तथा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 1/3 हिस्से पर प्रार्थीगण द्वारा ही काश्त कर बुवाई की हुई है। विधि का यह स्थापित सिद्धान्त है कि सह-संयुक्त सामलाती के सह खातेदारान का प्रत्येक इंच भूमि में सह - संयुक्त हक अधिकार कब्जा होता है। मौके पर प्रार्थीगण द्वारा खेत में काश्त के समय रहने हेतु झुपा भी बनाया हुआ है, प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण द्वारा हर वर्ष सहसंयुक्त सामलाती में अपने अपने हिस्से की भूमि पर कृषि कर बुवाई इत्यादी की जाती रही है, उपरोक्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण का 1/3 हिस्से काब्जा काश्त पर बिना किसी दखल हस्तक्षेप बाधा अवरोध के कायम रहा व है, लेकिन प्रतिवादी सं. 1 ता 7/5 की नियत शुरू से अपने हिस्से से अधिक की भूमि पर अतिक्रमण कर प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि दखल कर प्रार्थीगण के हिस्से को हड़प करने की रही है। जबकि विप्रार्थीगण को ऐसा करने का

सहायक कलेक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा

तर प्राप्त नहीं है। वादग्रस्त कृषि भूमि में प्राथीगण संज्ञ की भांति अपने हिस्से में कोई भी देखरेख करने के लिए दिनांक 21.8.2017 को गया जौ देखा की प्रतिवादी सं 1 को प्राथीगण के हिस्से की कृषि भूमि में दिनांक 20.8.2017 को सत्री में झुपि रखकर प्राथीगण को एवं कोई फसल को हटाय कर प्राथीगण के हिस्से की कृषि भूमि में दखल करने की से आपराधिक घटना कारित की, जिसके विरुद्ध वादी सं. 1 ने पुलिस शान्त पक्षधर में पेश की, प्रतिवादी सं. 1 ता 7/5 अपने हिस्से से ज्यादा भूमि पर अतिक्रमण कर प्राथीगण से में दखल हस्तक्षेप कर प्राथीगण के हिस्से को हटाय करना चाहते है, जिस हेतु अभी भी पर ऐसा करने हेतु उत्तार है। जिसका विप्राथीगण को कोई अधिकार नहीं है ऐसी स्थिति में गण द्वारा न्यायालय में बंटवाडे का वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो जाने न्यायालय में शायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया गया।

प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्राथी के पक्ष में एवं विप्राथीगण के विरुद्ध दौरान दावा इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विप्राथीगण स्वयं उनके एजेन्ट, मजदूर ठेकेदार इत्यादि वादग्रस्त सहखातेदार कृषि भूमि के 546 रकबा 108 बीघा 09 दिस्वा अवस्थित है, उपरोक्त कृषि भूमि में प्राथीगण का सहसयुक्त सामंजस्य में 1/3 हिस्सा बराबर 36 बीघा 03 दिस्वा प्राथी के कब्जा कास्त में किसी तरह का मन गठन कानून हाथ में लेकर, अवैध एवं अनाधिकृत तरीके से अतिचार एवं कोई दखल /हस्तक्षेप स्वयं प्राथी के विधि पूर्ण कब्जा कास्त खातेदारी की वादग्रस्त सहखातेदार कृषि भूमि में अवैध अधिार कर देते है तो प्राथी को अपार अपरिमित क्षति होगी। जिसका मूल्यांकन मुद्दा में करना सम्भव नहीं होगा। यदि दौरान दावा विप्राथीगण को अवैध एवं अनाधिकृत दखल/हस्तक्षेप करने से निषेधित एवं निवारित किया जा तो विप्राथीगण को कोई हानि नहीं होगी। इस प्रकार सुविधा का संतुलन एवं साम्य का पवित्र सिद्धान्त काबिल खातेदार टैनेन्ट प्राथी के हक/ पक्ष में ही विद्यमान है।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विप्राथी को नोटिस जारी किया गया जिस पर विप्राथी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए विप्राथीगण की ओर से जबाब पेश किया गया। जबाब में बताया कि वादग्रस्त भूमि में विप्राथीगण की रहवासिया दागीया भी बनी हुई है पूर्व में विगत 40 वर्षों से मौके पर काबिल अनुरूप बंटवाडा होने से उसी ताफिक कब्जा कास्त रहा है व उपरोक्त खाते खसरा की जमीन पर कमी झूपा नहीं बनाया है झूपा व बुवाई के मनगठन तथा अंकित किये है। विप्राथीगण द्वारा प्राथीगण का दखल हस्तक्षेप व बाधा अवरोध नहीं पहुंचाई गई विप्राथीगण अपने कब्जा कास्त की भूमि पर पीढीयों से कास्त कर उपयोग व उपयोग में लेते आ रहे है। विप्राथीगण द्वारा उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया गया प्राथीगण द्वारा किया व मनगठन तथा अंकित किये है प्राथीगण विप्राथीगण के विरुद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से हम विप्राथीगण को अत्यधिक आर्थिक हानी होगी प्राथीगण को किसी प्रकार की हानी होने का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि प्राथीगण मौके पर कास्त नहीं है सुविधा का संतुलन अपूर्ण्य क्षति तथा स्टाम्प का पवित्र सिद्धान्त प्राथीगण के पक्ष न होकर विप्राथीगण के पक्ष में विध्यमान होने से प्रार्थना पत्र काबिल खारीज के है।

हमने दोनो पक्षों के वकीलों की बहस को सुना व मनन किया पत्रावली के संलग्न दस्तावेजा जमाबंदी संवत 2070-2073 का अवलोकन किया गया दोनो पक्षों के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन व अध्ययन किया गया। चूंकि प्राथीगण उक्त भूमि के सहखातेदार 1/3 हिस्से के रेकार्डेड खातेदार है यदि उनके संयुक्त कब्जा कास्त में विप्राथीगण के द्वारा दखल किया जाता है तो प्राथी को अपूर्ण्य क्षति होने की संभावना है। इस प्रकार दौरान दावा अस्थायी निषेधाज्ञा आज्ञा जारी करने के सभी आधार इस स्तर पर प्राथीगणों के पक्ष में पाये जाते है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्राथीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर विप्राथीगण को इस आशय की अस्थाई आज्ञा दौरान दावा से पाबन्द किया  
सहायक कलेक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा

वैश्वानर सख्त मीठा मण्डलार्ड में अधिग्रहण क्षेत्र क्रमा संख्या 548 रकबा 108  
व में शरीरक के संयुक्त 1/3 हिस्सा के कब्जा काय्य व उपयोग-उपयोग में किसी  
एवं टखल/इसकाय कयित नही करे और न अन्य किसी से ऐसा करने व वादक पर  
न इस्ते किसी तीसरे पट्टा का इक सजृति नही करे तथा मीठा एव अधिग्रहण को यथावत

अदालत कृते न्यायालय सुनवा गया।

न्यायली फैसल सुनार होकर के दायित्व दायर हो ।

(माननीय न्याय)  
जुज न्यायालय  
उ.प्र. उ. न्यायालय

